मैसर्स भगवती वनस्पति ट्रेडर्स

बनाम

सीनियर सुपरिन.ऑफ़ पोस्ट ऑफिस

मेरठ

(सिविल अपील सं. 4854/2009)

10 अक्टूबर, 2014

[जगदीश सिंह खेहर, सी. नागप्पन जे.जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: मुआवजा सी एक स्वामित्व कंपनी द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) की खरीद-परिपक्वता पर, प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा परिपक्व राशि का भुगतान इस आधार पर नहीं किया जाता है कि एनएससी केवल एक व्यक्ति के नाम पर जारी किया जा सकता है, और यह कि, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के नाम पर लिया गया एनएससी डी वैध नहीं था -प्रोप्राइटर कंसर्न के नाम पर एनएससी जारी करते समय की गई। अनियमितता को अधिकारियों द्वारा प्रोप्राइटर के नाम को प्रतिस्थापित करके आसानी से ठीक किया जा सकता था -अधिकारियों द्वारा अपनाई गई कठोरता गलत थी -अधिकारियों ने एक प्रमाणपत्र जारी किया जिसे वे जारी नहीं कर सकते थे और इसलिए, उन्हें

जमा राशि को बरकरार रखकर खुद को समृद्ध बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती -अधिकारियों को अनियमितता को नियमित करने के लिए साधन तैयार करने चाहिए थे -जिला फोरम ने अधिकारियों को निर्देश देने में सही किया था परिपक्वता राशि 12% ब्याज के साथ और 5000/-रूपये मुआवजे के रूप में, और 2000/-रूपये की लागत का भी स्वामित्व वाली संस्था को भुगतान करें, जिसे राज्य और राष्ट्रीय आयोग द्वारा गलत तरीके से अलग रखा गया था।

रोकः की प्रयोज्यता -जहां सूचना के एक ही स्त्रोत वाले दो लोग एक ही सत्य का दावा करते हैं या एक ही समय में एक ही झूठ का दावा करने के लिए सहमत होते हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ रोका नहीं जा सकता है।

अपील स्वीकार

अभीनिर्धारित: 1. मैसर्स. भगवती वनस्पति ट्रेडर्स, हमारे सामने अपीलकर्ता, एक स्वामित्व वाली कंपनी है। श्री बीके गर्ग इसके एकमात्र मालिक हैं। 28.4.1995 को मै. भगवती वनस्पति ट्रेडर्स ने रु. 5,000/-का निवेश करके छह साल का एक राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (जिसे इसके बाद एनएससी कहा जाएगा) क्रमांक 6NS/06DD 387742 खरीदा। उपरोक्त एनएससी 28.4.2001 को परिपक्व होनी थी। दिनांक 28.4.2001 को देय परिपक्वता राशि 10,075/-रुपये थी।

2. चूंकि मै. भगवती वनस्पति ट्रेडर्स को परिपक्वता पर देय राशि का भुगतान नहीं किया गया, बीके गर्ग ने उस कार्यालय में बार-बार चक्कर लगाए जहां से एनएससी खरीदी गई थी। उन्हें सूचित किया गया कि एनएससी केवल एक व्यक्ति के नाम पर जारी किया जा सकता है, और एनएससी मेसर्स के नाम पर लिया गया है। भगवती वनस्पति ट्रेडर्स, वैध नहीं था। उन्हें यह भी बताया गया कि मामला सलाह के लिए पोस्ट मास्टर जनरल, बरेली को भेजा गया है और परिपक्वता राशि के भुगतान के सवाल पर बरेली से इनपुट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा। काफी समय तक इंतजार करने के बाद, और यह महसूस करने पर कि प्रतिवादी की ओर से कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई, बीके गर्ग ने पोस्ट मास्टर जनरल, बरेली के कार्यालय का दौरा किया। बरेली में उन्हें सूचित किया गया कि मामला महानिदेशक (डाक), डाक विभाग, नई दिल्ली को भेजा गया है और उन्हें महानिदेशक (डाक) के निर्णय का इंतजार करना होगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी, बिना किसी सार्थक परिणाम के, मैसर्स। भगवती वनस्पति ट्रेडर्स वरीय शिकायत प्रकरण क्र. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, मेरठ (इसके बाद जिला फोरम के रूप में संदर्भित) के समक्ष 2004 का 513। जिला फोरम ने अपने आदेश दिनांक 1.2.2007 द्वारा मेसर्स के दावे को स्वीकार कर लिया। भगवती वनस्पति ट्रेडर्स, और तदनुसार, प्रतिवादी को परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12% ब्याज के साथ 10,075/-रुपये की

परिपक्वता राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी को अतिरिक्त रूप से अपीलकर्ता स्वामित्व कंपनी को मुआवजे के रूप में 5,000/-रुपये और 2,000/-रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

3. जिला फोरम द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 1.2.2007 से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, मेरठ ने अपील सं. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लखनऊ के समक्ष 2007 का 460। उपरोक्त अपील को राज्य आयोग ने अपने आदेश दिनांक 21.1.2008 द्वारा अनुमति दी थी। इसके बाद अपीलकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका संख्या को प्राथमिकता दी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के समक्ष 2008 का 1456। राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 4.9.2008 के आदेश के तहत पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। दिनांक 4.9.2008 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील की विशेष अनुमति इस न्यायालय द्वारा 27.7.2009 को प्रदान की गई थी।

4. राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि वे इस तथ्य पर आधारित थे कि एनएससी मैसर्स द्वारा खरीदा गया था। भगवती वनस्पति ट्रेडर्स में एक अनियमितता थी, क्योंकि एनएससी केवल एक व्यक्ति द्वारा ही खरीदा जा सकता था, और इसे किसी चिंता, फर्म, संस्थान, बैंकिंग संस्थान या कंपनी आदि के नाम पर जारी नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त के कारण अनियमितता,

प्रतिवादी ने डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम, 1981 के नियम 17 पर भरोसा किया। उपरोक्त नियम यहां से निकाला जा रहा है:-

"17. नियमों के उल्लंघन में खोला गया खाता: -नियम 16 के प्रावधान के अधीन, जहां कोई खाता उस समय लागू और डाकघर बचत बैंक में रखे गए खाते पर लागू किसी भी प्रासंगिक नियम के उल्लंघन में खोला गया पाया जाता है, संबंधित प्रमुख बचत बैंक, किसी भी समय, खाता बंद कर सकता है और खाते में जमा राशि जमाकर्ता को बिना ब्याज के वापस कर सकता है।

उपरोक्त के अलावा, प्रतिवादी ने इस न्यायालय द्वारा पोस्ट मास्टर, दरगामिट्टा एचपीओ, नेल्लर बनाम राजा प्रमीलम्मा, (1998) 9 एससीसी 706 में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया था, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा था: -"लेकिन जैसा कि यह अनुबंध भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के विपरीत था और यह कर्मचारियों की असावधानी के कारण था। मेरी राय में यह गैरकानूनी और शून्य होने के कारण भारत सरकार के लिए बाध्यकारी कोई अनुबंध नहीं बनता है। इस प्रकार यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(जी) में परिभाषित कानून के संदर्भ में या अनुबंध के संदर्भ में सेवा में कमी का मामला नहीं है।

(जोर हमारा है)

सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने, यहां ऊपर दिए गए फैसले के अलावा, इस न्यायालय द्वारा अरुलमिघु धंदायाधपनीस्वामी थिरुकोइल, पलानी, तमिलनाडु बनाम डाक महानिदेशक मामले में दिए गए एक हालिया फैसले पर भरोसा जताया। कार्यालय, डाक विभाग एवं अन्य, (2011) 13 एससीसी 220, और उसमें दर्ज निम्नलिखित निष्कर्षों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया;-

"18. राजा प्रमीलम्मा मामले, (1998) 9 एससीसी 706 में इस न्यायालय ने माना कि भले ही प्रमाणपत्रों में भारत सरकार और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र धारकों के बीच अनुबंध की शर्तें शामिल थीं, अनुबंध की शर्तें अधिसूचना के विपरीत थीं और इसलिए अनुबंध की शर्तें गैरकानूनी और शून्य होने के कारण भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं थीं और इस प्रकार सरकार द्वारा प्रमाण पत्र में उल्लिखित दर पर ब्याज देने से इंकार करना कानून के संदर्भ में या सेवा में कमी का मामला नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(जी) के तहत परिभाषित अनुबंध। उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू है।

19. यह सच है कि जब अपीलकर्ता ने पांच साल की अवधि के लिए योजना के तहत 5.5.1995 से 16.8.1995 तक तीसरे प्रतिवादी के साथ एक बड़ी राशि जमा की, तो पोस्ट मास्टर की ओर से यह उचित था कि वह एक जमा पर लागू सही योजना का नोट। पोस्टमास्टर के लिए यह भी

संभव था कि वह रिकॉर्ड से पता लगा सकता था, सही योजना लागू कर सकता था और यदि अपीलकर्ता, एक संस्था होने के नाते, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं था, तो उन्हें उचित सलाह दी जाती। यद्यपि अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एस. अरविंद ने इस न्यायालय से तीसरे प्रतिवादी को उसकी गलती के लिए कुछ उचित राशि का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, क्योंकि ऐसा निर्देश नियमों के विपरीत होगा और ऐसी योजना के लिए ब्याज का भुगतान निषिद्ध है। नियम 17 के अनुसार, हम इसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।"

(जोर हमारा है)

राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा क्रमशः 21.1.2008 और 4.9.2008 के आक्षेपित आदेशों पर भरोसा करने वाले इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर, साथ ही, इस न्यायालय द्वारा दिए गए नवीनतम निर्णय के आधार पर अरुलमिघु धंदायाधपनीस्वामी थिरुकोइल मामले (सुप्रा) में, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील का जोरदार तर्क था कि अपीलकर्ता को परिपक्वता राशि जारी करने का कोई सवाल ही नहीं था।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील का यह भी तर्क था कि डाक अधिकारियों की गलती निर्दोष थी। अपीलकर्ता के दावे की जांच के बाद, प्रारंभिक जांच से पता चला कि एनएससी मेसर्स को जारी किया गया था। वेद बहादुर सिंह (डाक विभाग के कर्मचारी) द्वारा भगवती वनस्पति ट्रेडर्स।

उक्त कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर उसे विधिवत दण्डित किया गया। तदनुसार, यह दावा करने की कोशिश की गई कि ऐसा नहीं है कि, डाक अधिकारी जानबूझकर अपीलकर्ता को 28.4.1995 को उसके द्वारा खरीदे गए एनएससी के लाभों से वंचित कर रहे थे। विद्वान वकील के अनुसार, अपीलकर्ता को वंचित करना, अपीलकर्ता के कानूनी अधिकारों के शुद्ध निर्धारण पर आधारित था।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों पेश किया गया पहला तर्क इस न्यायालय द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (2001) 2 एससीसी 41 में दिए गए निर्णय पर आधारित था। जहाँ से विद्वान वकील ने हमारा ध्यान निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया:-

"20. आधुनिक समय में आचरण पर रोक पिकार्ड बनाम सियर्स, 1837 6 ई. में अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों से स्पष्ट होती है और एल. 469, और सरत चंदर डे बनाम गोपाल चंदर लाहा, (1891-92) 19 आईए 203 के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा इसके वास्तविक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने तक इसका क्रमिक विस्तार, जबकि इससे पहले सेटन लिंग कंपनी वी. लाफोन के मामले में लॉर्ड एशर 1887 19 क्यूबीडी 68, ने एस्टोपेल के सिद्धांत के तीन बुनियादी तत्वों को विकसित किया:

"सबसे पहले, जहां एक आदमी कपटपूर्ण गलत बयानी करता है और दूसरा व्यक्ति उस पर वास्तविक नुकसान पहुंचाता है: दूसरे, दूसरा वह हो सकता है जहां एक आदमी लापरवाही से गलत बयान देता है, हालांकि धोखाधड़ी के बिना और कोई अन्य व्यक्ति उस पर कार्य करता है: और तीसरा, वहां हो सकता है जिन परिस्थितियों में, बिना धोखाधड़ी और लापरवाही के गलत बयानी की जाती है, वहां एस्टॉपेल हो सकता है।

हालाँकि, लॉर्ड शैंड ने इस आशय में एक और तत्व जोड़ने की कृपा की कि ऐसे बयान दिए जा सकते हैं, जिन्होंने दूसरे पक्ष को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है, अन्यथा वह इससे दूर रहते और जिसे उचित रूप से गलत बयानी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में, क्रेन बनाम कोलोनियल म्युचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1920 28 सीएलआर 305 के मामले में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। डिक्सन, जे. ने ग्रंड्ट बनाम द में अपने फैसले में ग्रेट बोल्डर प्राइवेट गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, 1938 59 सीएलआर 641, ने कहा कि:

> "नुकसान को मापने में, या इसके अस्तित्व को प्रदर्शित करने में, प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने से पहले और बाद में, प्रतिनिधित्वकर्ता की स्थिति की तुलना नहीं

की जाती है, इस धारणा पर कि प्रतिनिधित्व को सत्य माना जाना है, रोक का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा तभी होता है जब प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधित्व में निहित धारणा को अस्वीकार करना चाहता है कि एक रोक उत्पन्न होती है, और हानि के प्रश्न पर तदनुसार विचार किया जाता है, उस स्थिति के प्रकाश में जो प्रतिनिधित्वकर्ता को अस्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिनिधित्व की सच्चाई।"

(इस संदर्भ में स्पेंसर बोवर और टर्नर: रिप्रजेंटेशन द्वारा एस्टॉपेल, तीसरा संस्करण देखें)। लॉर्ड डेनिंग ने सेंट्रल न्यूबरी कार ऑक्शन्स लिमिटेड बनाम यूनिटी फाइनेंस लिमिटेड, 1956 (3) ऑल ईआर 905 के मामले में भी 'नुकसान' के परीक्षण से संबंधित लॉर्ड डिक्सन, जे. के विचार को स्वीकार किया है। इसका प्रभाव यह है कि क्या यह अन्यायपूर्ण या असमान प्रतीत होता है कि प्रतिनिधित्वकर्ता को अब अपने प्रतिनिधित्व से पीछे हटने की अनुमति दी जानी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिनिधित्वकर्ता ने प्रतिनिधित्व पर भरोसा करते हुए क्या किया है या करने से परहेज किया है, संक्षेप में, रोक लगाने वाले पक्ष को अवश्य ही उनके अहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। जब तक धारणा

का पालन किया जाता है, तब तक जिस पक्ष ने इस पर विश्वास करके स्थिति को बदल दिया, वह शिकायत नहीं कर सकता। उनकी शिकायत यह है कि जब बाद में दूसरा पक्ष मामलों की एक अलग स्थिति बनाता है, तो उसके खिलाफ अधिकार के दावे का आधार होता है, अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो उसकी अपनी स्थिति में मूल परिवर्तन एक नुकसान के रूप में काम करेगा, (ग्रंड्ट्स: उच्च न्यायालय के अनुसार) ऑस्ट्रेलिया का (सुप्रा))।

21. फिप्सन ऑन एविडेंस (चौदहवें संस्करण) में आचरण द्वारा रोक के संबंध में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं।

"आचरण द्वारा रोक, या, जैसा कि उन्हें अभी भी कभी-कभी कहा जाता है, पैस में पदार्थ द्वारा रोक, प्राचीन काल में बदनामी के कार्य थे जो किसी कार्य के निष्पादन से कम गंभीर और औपचारिक नहीं थे, जैसे कि सेसीन की देनदारी, प्रवेश, एक संपत्ति की स्वीकृति और जैसे, और क्या किसी पक्ष ने इस प्रकार के कार्य में सहमति व्यक्त की थी या नहीं, यह एक ऐसा मामला माना जाता था जिसे सुनिश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती थी, और फिर कानूनी परिणाम सामने आते थे (ल्योन बनाम रीड, (1844) 13 एम एंड डब्ल्यू 285 (पृ. 309 पर)। हालाँकि, आधुनिक समय में इस सिद्धांत का विस्तार किया गया है ताकि किसी पक्ष द्वारा व्यावहारिक रूप से किसी भी कार्य या बयान को अपनाया जा सके,

जिसे अस्वीकार करने की अनुमति देना अनुचित होगा। नियम को आधिकारिक तौर पर इस प्रकार कहा गया है इस प्रकार है: 'जहां कोई अपने शब्दों या आचरण से जानबूझकर किसी अन्य को चीजों की एक निश्चित स्थिति के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है और उसे उस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ताकि उसकी अपनी पिछली स्थिति को बदल दिया जा सके, तो पहले वाले को बाद वाले के खिलाफ विरोध करने से निष्कर्ष निकाला जाता है। एक ही समय में विद्यमान चीज़ों की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ।' (पिकार्ड बनाम सियर्स (सुप्रा))। और किसी व्यक्ति का वास्तविक इरादा जो भी हो, उसे जानबूझकर कार्य करने वाला माना जाता है 'यदि वह ऐसा आचरण करता है कि एक उचित व्यक्ति प्रतिनिधित्व को सच मान लेगा और विश्वास करेगा कि इसका मतलब यह था कि उसे इस पर कार्य करना चाहिए।' (फ्रीमैन बनाम कुक, 1848 (2) एक्सच. 654: पृष्ठ 663 पर)।

जहां आचरण लापरवाहीपूर्ण है या पूरी तरह से चूक से युक्त है, वहां गुमराह व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होना चाहिए (मर्केंटाइल बैंक बनाम सेंट्रल बैंक, 1938 एसी 287 पृष्ठ 304 पर, और नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक बनाम बार्कलेज बैंक इंटरनेशनल, 1975 क्यूबी 654) . यह सिद्धांत एस्टोपेल के बाकी कानून के साथ अजीब तरह से मेल खाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तुलनात्मक रूप से हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा, कम से

कम निहितार्थ द्वारा, इसकी पुनः पुष्टि की गई है (मूर्गेट मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड बनाम ट्विचिंग्स, (1977) एसी 890) . स्पष्टीकरण में कोई संदेह नहीं है कि रोक के इस पहलू को उचित रूप से तथाकथित रोक के बजाय लापरवाह अभ्यावेदन से संबंधित कानून का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। यदि जानकारी के एक ही स्रोत वाले दो लोग एक ही सत्य का दावा करते हैं या एक ही समय में एक ही झूठ का दावा करने के लिए सहमत होते हैं, तो किसी को भी दूसरे के मुकाबले किसी अन्य समय पर अलग-अलग दावा करने से नहीं रोका जा सकता है (स्क्वायर बनाम स्क्वायर, 1935 पी. 120) "

22. इसका केवल अवलोकन करने से पता चलता है कि आचरण द्वारा रोक का मुद्दा केवल तभी उपलब्ध माना जा सकता है जब कोई सटीक और स्पष्ट प्रतिनिधित्व हो और उस स्कोर पर एक और सवाल उठता है कि क्या ऐसा है क्या कोई स्पष्ट आश्वासन था जो आश्वस्त व्यक्ति को अपनी स्थिति या स्थिति बदलने के लिए प्रेरित कर रहा था। हालाँकि, प्रासंगिक तथ्य अन्यथा दर्शाते हैं। मूल्य संरक्षण के लाभ के लिए आवेदन पत्र के अनुलग्नक 2 में निम्नलिखित आशय का एक वचन शामिल है:-

"हम इसके द्वारा ईईपीसी को मूल्य संरक्षण के लिए हमारे आवेदन के विरुद्ध भुगतान की गई राशि को पूर्ण या उसके हिस्से में रुपये वापस करने का वचन देते हैं। हमारे द्वारा किए गए निर्यात के विरुद्ध दिनांकित आवेदन

के संदर्भ में...यदि हमारे उपर्युक्त दावों के विरुद्ध हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई विशेष घोषणा/प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है या कोई अतिरिक्त भुगतान निरीक्षण/गलत गणना के कारण किया गया निर्धारित किया जाता है आदि किसी भी समय. हम रिफंड मांगने वाले नोटिस की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर राशि वापस करने का भी वचन देते हैं, अन्यथा गलती से भुगतान की गई या अधिक भुगतान की गई राशि ईईपीसी या लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा निर्यात लाभ के लिए किसी अन्य दावे से वसूल की जाएगी या समायोजित की जाएगी। सीसीआई और सी के और इस स्कोर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि गलती से भुगतान की गई या अधिक भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए धनवापसी के लिए एक विशिष्ट उपक्रम होने की स्थिति में, हमारे विचार में कोई रोक होने का सवाल ही नहीं उठता। इस संदर्भ में पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार काफी महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से लौह एवं इस्पात के सहायक विकास आयुक्त का पत्र दिनांक 30.11.1990 और उसका उत्तर दिनांक 8.3.1991 जो स्पष्ट रूप से जेपीसी मूल्य का भुगतान न करने के तथ्य को दर्ज करता है।

(जोर हमारा है)

उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का जोरदार तर्क था कि रोक का नियम अपीलकर्ता की सहायता के लिए आएगा, क्योंकि अपीलकर्ता को जानबूझकर एनएससी खरीदने की अनुमति

दी गई है। यह कहकर कि एनएससी की खरीद में कुछ अनियमितता हुई है, परिपक्वता राशि के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता।

7. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में रोक के सिद्धांत की प्रयोज्यता को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। अपीलकर्ता को कभी भी कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया है। एनएससी खरीदने का निर्णय अपीलकर्ता का व्यक्तिगत निर्णय था। यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता को कोई कपटपूर्ण अभ्यावेदन दिया गया था। यह भी नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता को लापरवाही से गलत बयान दिया गया था। वर्तमान मामले में रोक का नियम केवल प्रतिवादी के कुछ आचरण पर आधारित हो सकता है, जिसने जानबूझकर अपीलकर्ता को एनएससी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। दुर्भाग्य से, अपीलकर्ता के लिए, ऐसा कोई जानबूझकर किया गया आचरण हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। मामले के तात्कालिक पहलू पर अपना विचारशील विचार करने के बाद, हमें लगता है कि यह मामला मूरगेट मर्कंटाइल कंपनी लिमिटेड बनाम ट्विचिंग्स, (1977) एसी 890 में विकसित प्रस्ताव द्वारा शासित होगा, जहां दो लोग एक जैसे हैं सूचना का स्रोत एक ही सत्य का दावा करता है या एक ही समय में एक ही झूठ का दावा करने के लिए सहमत होता है, किसी को भी दूसरे के विरुद्ध रोका नहीं जा सकता है। इसलिए, हालांकि इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है, कि एनएससी जारी करने वाले

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि यह केवल ऐसे व्यक्तियों को जारी किया गया था जो इसे खरीदने के लिए कानून में पात्र थे, फिर भी यहां ऊपर दिए गए नियम 17 के आदेश के अनुसार, जिसका अधिकार चुनौती का विषय नहीं है, हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि किसी भी उपयोगी लाभ के लिए अपीलकर्ता के आदेश पर रोक के नियम पर भरोसा किया जा सकता है।

8. यहां ऊपर दिए गए नियम 17 के अधिदेश को दूर करने के लिए, साथ ही, राजा प्रमीलम्मा मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, और अरुलमिघु धंदायाधपनिस्वामी थिरुकोइल मामले (सुप्रा) में घोषित कानून के प्रस्ताव को दूर करने के लिए, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील ने रखा। अशोक ट्रांसपोर्ट एजेंसी बनाम अवधेश कुमार और अन्य, (1998) 5 एससीसी 567 में इस न्यायालय के फैसले पर जोरदार निर्भरता। उन्होंने उसमें दर्ज निम्नलिखित टिप्पणियों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया:-

"6. एक साझेदारी फर्म किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली मालिकाना कंपनी से भिन्न होती है। एक साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। हालांकि साझेदारी एक न्यायिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन आदेश XXX नियम 1 सीपीसी साझेदारी फर्म के

भागीदारों को फर्म के नाम पर मुकदमा करने या मुकदमा करने में सक्षम बनाता है । एक मालिकाना संस्था केवल व्यवसाय का नाम है जिसमें व्यवसाय का मालिक व्यवसाय चलाता है। किसी मालिकाना प्रतिष्ठान द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा व्यवसाय के मालिक द्वारा या उसके विरुद्ध होता है। किसी मालिकाना प्रतिष्ठान के मालिक की मृत्यु की स्थिति में, मालिक के कानूनी प्रतिनिधि ही मालिकाना व्यवसाय के लेनदेन के संबंध में मुकदमा कर सकते हैं या मुकदमा दायर कर सकते हैं। ऑर्डर XXX के नियम 10 के प्रावधान, जो ऑर्डर XXX के प्रावधानों को एक मालिकाना कंपनी पर लागू करते हैं, एक मालिकाना व्यवसाय के मालिक को उसकी मालिकाना कंपनी के व्यावसायिक नाम पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाते हैं। जिस वास्तविक पक्ष पर मुकदमा दायर किया जा रहा है वह उक्त व्यवसाय का मालिक है। उक्त प्रावधान का मालिकाना व्यवसाय को साझेदारी फर्म में परिवर्तित करने का प्रभाव नहीं है। आदेश XXX के नियम 4 के प्रावधान ऐसे मुकदमे पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि आदेश XXX नियम 10 के आधार पर आदेश XXX के अन्य प्रावधान मालिकाना व्यवसाय के मालिक के खिलाफ एक मुकदमे पर लागू होते हैं "जहां तक ऐसे मामले की प्रकृति अनुमति देती है" . इसका मतलब यह है कि आदेश XXX के केवल उन्हीं प्रावधानों को मालिकाना कंपनी पर लागू किया जा सकता है जिन्हें मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा सकता है।

(जोर हमारा है)

उपरोक्त निर्णय में दर्ज टिप्पणियों के आधार पर, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा पेश किया गया दूसरा तर्क यह था कि कुल मिलाकर, एक एकल स्वामित्व वाली कंपनी किसी की ओर से एक व्यापार नाम के काल्पनिक उपयोग की अनुमति देती है। व्यक्तिगत। यह तर्क दिया गया कि सच तो यह है कि केवल एक ही व्यक्ति एकल स्वामित्व वाली संस्था का मालिक है। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था का नाम, फिर से एकमात्र मालिक के नाम से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अपीलकर्ता द्वारा खरीदा गया एनएससी सख्ती से कानून के आदेश के अनुरूप होगा। विद्वान वकील के अनुसार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनएससी खरीदते समय व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है या मालिकाना हक का। यह इंगित किया गया था, कि यदि प्रतिवादी व्यापार नाम को स्वीकार करने में सहमत नहीं था, तो प्रतिवादी को मैसर्स के नाम को प्रतिस्थापित करके एनएससी को सही करना चाहिए था। भगवती वनस्पति ट्रेडर्स, इसके एकमात्र मालिक बीके गर्ग हैं।

9. हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों पेश किए गए दूसरे तर्क में योग्यता पाते हैं। यह वास्तव में सच है कि एनएससी मेसर्स के

नाम पर खरीदा गया था। भगवती वनस्पति ट्रेडर्स. यह भी उतना ही सत्य है कि मै. भगवती वनस्पति ट्रेडर्स बीके गर्ग की एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी है, और इस प्रकार, मेसर्स के नाम पर एनएससी जारी करते समय की गई अनियमितता। भगवती वनस्पति ट्रेडर्स, को मेसर्स का नाम प्रतिस्थापित करके आसानी से ठीक किया जा सकता था। बीके गर्ग के साथ भगवती वनस्पति ट्रेडर्स। क्योंकि, एकल स्वामित्व वाली कंपनी में एक व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर एक काल्पनिक व्यापार नाम का उपयोग करता है। अधिकारियों द्वारा अपनाई गई सख्ती स्पष्ट रूप से समझ से परे है। डाक अधिकारियों ने मैसर्स को अनुमति दे दी है। वर्ष 1995 में एनएससी खरीदने के लिए भगवती वनस्पति ट्रेडर्स, वर्ष 2001 में इसकी परिपक्वता के बाद वैध रूप से अनियमितता की चुनौती नहीं उठा सकते थे, खासकर जब अनियमितता का इलाज संभव था। कानूनी तौर पर, डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम, 1981 का नियम 17 केवल तभी लागू होगा जब किसी आवेदक को किसी योजना के तहत निर्धारित राशि से अधिक की अनुमति अनियमित रूप से दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि योजना Y% के ब्याज पर विचार करती है और जारी किए गए प्रमाणपत्र में परिपक्वता पर देय Y+2% का ब्याज दर्ज किया गया है, तो उपरोक्त अनियमितता के कारण प्रमाणपत्र धारक को समग्र रूप से ब्याज से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसे केवल 2% से वंचित किया जा सकता है, अर्थात, योजना के तहत अनुमेय ब्याज से अधिक राशि। एक प्रमाणपत्र

धारक को, उपरोक्त उदाहरण में, नियम 17 के बावजूद, योजना के अनुरूप, Y% पर ब्याज का दावा करने का पूर्ण अधिकार होगा। आमतौर पर, जब अधिकारियों ने एक प्रमाणपत्र जारी किया है जिसे वे जारी नहीं कर सकते थे, उन्हें अपनी जमा राशि बरकरार रखकर खुद को समृद्ध बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह तब संभव हो सकता है जब लेन-देन दिखावटी या पूरी तरह से अवैध हो। ऐसा नहीं है, यदि अनियमितता का इलाज संभव है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि संभव हो तो, डाक अधिकारियों को अनियमितता को नियमित करने के उपाय खोजने चाहिए।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, राजा प्रमीलम्मा मामले (सुप्रा) और अरुलमिघु धंदायाधपनीस्वामी थिरुकोइल मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर, अपीलकर्ता को राहत देने से इनकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। यहां ऊपर हमारे द्वारा निर्धारित परिप्रेक्ष्य में जांच की गई है। दोनों में से किसी भी फैसले में एनएससी में संशोधन की मांग नहीं की गई। कानून का तात्कालिक प्रस्ताव भी, ऊपर व्यक्त तरीके से, प्रमाणपत्र धारकों की ओर से पेश नहीं किया गया था।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बताए गए दोष को नियमित करने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि मै. भगवती वनस्पति ट्रेडर्स, निश्चित रूप से बीके गर्ग की एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी है। डाक अधिकारियों को स्वयं बीके गर्ग के एक अभ्यावेदन के माध्यम से एनएससी

में नाम बदलने का आग्रह करना चाहिए था। इस तरह का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, कथित अनियमितता ठीक हो जाएगी, और जमा के लाभार्थी को वैध रूप से उसका फल मिलेगा। उपरोक्त सरल पाठ्यक्रम को अपनाने के बजाय, डाक अधिकारियों ने योजना की शर्तों की सख्ती से और कठोरता से व्याख्या करने का विकल्प चुना। इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता संस्था के एकमात्र मालिक, यानी बीके गर्ग, द्वारा किए गए निवेश के वैध दावों को अस्वीकार कर दिया गया। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक, मेरठ को एम के नाम पर जारी एनएससी को सही करने का निर्देश देना उचित और उचित मानते हैं। /एस। भगवती वनस्पति ट्रेडर्स ने अपीलकर्ता के नाम को बीके गर्ग के नाम से प्रतिस्थापित करके।

12. अनियमितता ठीक कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि जिला फोरम द्वारा पारित आदेश के अनुसार, बीके गर्ग को अब उनके सभी भुगतान जारी कर दिए जाएंगे। तदनुसार, प्रतिवादी को बीके गर्ग को परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक 12% ब्याज के साथ 10,075/- रुपये की परिपक्वता राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। वह मुआवजे के रूप में 5,000/-रुपये का हकदार होगा, जैसा कि जिला फोरम

ने उसे दिया था। इसके अलावा, हम उसे 10,000/-रुपये का मुकदमा खर्च देना उचित मानते हैं। उपरोक्त पूरी राशि इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर मेसर्स भगवती वनस्पति ट्रेडर्स के एकमात्र मालिक बीके गर्ग को जारी की जानी चाहिए।

13. उपरोक्त शर्तों के तहत अपील को स्वीकार किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल ललवाणी आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।